



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]
No. 141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सं.का.नि. 208(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं0आ0 205”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2, आदेश 2005 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संघित निधि पर भास्ति होंगी :-

राज्य		रुपए करोड़ में
(1)		(2)
1.	अरुणाचल प्रदेश	211.28
2.	हिमाचल प्रदेश	605.07
3.	जम्मू - कश्मीर	1979.34

	(1)	(2)
4.	मणिपुर	287.86
5.	मेघालय	235.18
6.	मिजोरम	287.36
7.	नागालैंड	649.20
8.	सिक्किम	139.31
9.	त्रिपुरा	388.01

(2) उपपैरा (1) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए सिफारिश की गई रकमों का 85 प्रतिशत हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदान के 15 प्रतिशत को रोकने और उतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक राज्य के सामने यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सहायता अनुदान, राज्यों के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि से चालू वर्ष के दौरान दिया गया था :-

	राज्य	रुपए करोड़ में
	(1)	(2)
1.	अरुणाचल प्रदेश	38.41
2.	बिहार	411.41
3.	छत्तीसगढ़	2.74
4.	गुजरात	55.40
5.	हरियाणा	55.17
6.	हिमाचल प्रदेश	156.96
7.	जम्मू - कश्मीर	354.31
8.	झारखंड	42.95
9.	कर्नाटक	184.94
10.	मध्य प्रदेश	304.97
11.	मणिपुर	107.50
12.	मेघालय	91.38
13.	मिजोरम	53.43
14.	नागालैंड	114.58
15.	उड़ीसा	50.91
16.	पंजाब	7.47

	(1)	(2)
17.	राजस्थान	120.38
18.	सिक्किम	76.45
19.	तमिलनाडु	181.06
20.	त्रिपुरा	75.02
21.	उत्तर प्रदेश	174.34
22.	उत्तरांचल	24.59
23.	पश्चिमी बंगाल	207.03

(4) उपपैरा (1) और उपपैरा (3) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति ।

^

[फा. सं. 19(3)/05-वि. I]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 208(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

“C.O.205”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 2 ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2005.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified below, the sums specified against it—

State (1)	Rupees in crores (2)
1. Arunchal Pradesh	211.28
2. Himachal Pradesh	605.07
3. Jammu and Kashmir	1979.34
4. Manipur	287.86
5. Meghalaya	235.18
6. Mizoram	287.36
7. Nagaland	649.20
8. Sikkim	139.31
9. Tripura	388.01.

(2) The sums specified in column (2) of sub-paragraph (1) represent 85 per cent. of the amount recommended by the Eleventh Finance Commission for the year 2004-05. The Eleventh Finance Commission in its last report had recommended withholding of 15 per cent. of the grant recommended to the States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States.

(3) The following grants-in-aid as specified against each State were released during current year from Incentive Fund based on the fiscal performance of States during 2001-02, 2002-03, 2003-04 and 2004-05:—

State (1)	Rupees in crores (2)
1. Arunchal Pradesh	38.41
2. Bihar	411.41
3. Chattisgarh	7.74
4. Gujarat	55.40
5. Haryana	55.17
6. Himachal Pradesh	156.96
7. Jammu and Kashmir	354.31
8. Jharkhand	42.95
9. Karnataka	184.94
10. Madhya Pradesh	304.97
11. Manipur	107.50
12. Meghalaya	91.38
13. Mizoram	53.43
14. Nagaland	114.58
15. Orissa	50.91
16. Punjab	7.47
17. Rajasthan	120.38
18. Sikkim	76.45
19. Tamil Nadu	181.06
20. Tripura	75.02
21. Uttar Pradesh	174.34
22. Uttaranchal	24.59
23. West Bengal	207.03.

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraphs (1) and (3) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

Am

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(3)/05-L. I]

T.K. VISWANATHAN, Secy.